नई शिक्षा नीति एवं बदलते आयाम

*डॉ. कैलाश चन्द्र बुनकर

अच्छिन्नस्य ते देव सोम सुवीर्यस्य रायस्पोस्य ददितः स्याम।

सा प्रथमा संस्कृतिर्विश्ववारा स प्रथमो वरूणो मित्रोऽग्निः।।

शोध सारः–

यह शोध पत्र नई शिक्षा नीति 2020 के लिए संदर्भित है, जो मुख्यतः शिक्षा नीति 2020 की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करता है।

शिक्षा मानव विकास की एक प्रक्रिया है, जो व्यक्ति को समय एवं परिस्थिति के अनुकूल आचरण करना सिखाती है। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का सूचक है। जिस समाज की शिक्षा जितनी अधिक विकसित एवं सरल होगी, वह समाज उतना ही अधिक विकसित होगा। बालक तक शिक्षा पहुँचाने के लिए शिक्षक एवं पाठ्यक्रम की बड़ी भूमिका होती है। पाठ्यक्रम जितना अधिक सरल एवं व्यावहारिक होगा, उसकी मांग उतनी ही अधिक होगी व साथ ही अधिक से अधिक लोगों की सामाजिक विकास में सहभागिता बढ़ेगी।

जीवन में शिक्षा के महत्व को देखते हुए वर्तमान सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में नये बदलावों के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी है। नई शिक्षा नीति 2020 ने पिछली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जगह ले ली है। नई शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य भाषा दक्षता, सौन्दर्य बोध, नैतिक तर्क, डिजिटल साक्षरता, भारत बोध और चेतना का विकास करना है। बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को बढ़ने और विकसित होने के लिए एक समान अवसर प्रदान करना है तथा विद्यार्थियों में ज्ञान, कौशल, बुद्धि और आत्मविश्वास का सर्जन कर उनके दृष्टिकोणों का विकास करना है।

नई शिक्षा नीति, भारतीय जीवन मूल्यों पर आधारित होने के साथ–साथ भारतीय परम्पराओं, भारतीय संस्कृति एवं भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन, पुनर्स्थापन एवं प्रसार पर जोर देती है, जिससे यह भारत को एक समर्थ, गौरवशाली, आत्मनिर्भर बनाने में निश्चय ही प्रमुख भूमिका निभाएगी। शिक्षा नीति किसी भी राष्ट्र की मूलभूत आवश्यकता होती है, जिसमें अतीत का विश्लेषण, वर्तमान की आवश्यकता तथा भविष्य की संभावनाएँ निहित होती है।

'' विद्या वितर्कौ विज्ञानं स्मृतिः तत्परता क्रिया ।

यस्यैते षड्गुणास्तस्य नासाध्यमतिवर्तते ।। ''

मुख्य शब्दः– शिक्षा , राष्ट्रीय नीति 2029, डिजीटल यगु, सामाजिक परिवर्तन, परिकल्पना , कौशल, आत्मविश्वास, मौलिक परिवर्तन, निर्माण, प्रौद्योगिकी, नवाचार, अनुसंधान, जीवन मूल्य, पुर्नस्थापना, गुणवतायुक्त, मुल्याकंन परक इत्यादि।

पढ़ो, लिखा है दिवारो पर मेहनतकश का नारा।

पढ़ो, पोस्टर क्या कहता है, वो भी दोस्त तुम्हारा।। (सफदर हाश्मी, मशहूर गीत)

प्रस्तावनाः–

शिक्षा मानव जीवन के सर्वांगीण विकास का सर्वोत्तम साधन है। प्राचीन शिक्षा व्यवस्था को उच्च आदर्शों की उपलब्धि के लिए अग्रसर करती थी और उसके वैयक्तिक, सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन के सम्यक् विकास में सहायता करती थी। नई शिक्षा नीति मौजूदा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 29 जुलाई 2020 को अस्तित्व में आई । शिक्षा नीति में यह बदलाव कुल 24 वर्ष के अन्तराल के बाद किया गया है। लेकिन बदलाव जरूरी था और समय की जरूरत के अनुसार यह पहले से ही हो जाना चाहिए था। शिक्षा की व्यवस्था हर देश और काल में तत्कालीन सामाजिक – संस्कृतिक जीवन सन्दर्भो के अनुरूप बदलती रहनी चाहिए। कहा गया हैः–

एतद्देशप्रसूतस्य एकाशादग्रजन्मनः ।

स्वं स्वं चरित्रं शिक्षरेन् पृथिव्यां सर्वमानवाः। (मनु.2/20)

भारत की वर्तमान शिक्षा प्रणाली ब्रिटिश प्रतिरूप पर आधारित है, जिसे 1835 में लागू किया था। अंग्रेजी शासन की गलत शिक्षा नीति के कारण ही हमारा देश स्वतन्त्रता के इतने वर्षों बाद भी पर्याप्त विकास नहीं कर सका।

अंग्रेजी शासन में शिक्षा की स्थितिः– 1835 में वर्तमान शिक्षा प्रणाली की नींव रखी गई थी तब लॉर्ड मेकाले ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि ''अंग्रेजी शिक्षा का उद्देश्य भारत में प्रशासन को बिचौलियों की भूमिका निभाने तथा सरकारी कार्य के लिए भारत के लोगों को तैयार करना है। इसके फलस्वरूप एक सदी तक अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के प्रयोग में लाने के बाद भी 1935 में भारत साक्षरता के 10 प्रतिशत के ऑकडे को भी पार नहीं कर सका। स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय भी भारत की साक्षरता मात्र 13प्रतिशत ही थी। इस शिक्षा प्रणाली ने उच्च वर्गों को भारत के शेष समाज से पृथक रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसकी बुराईयों को सर्वप्रथम गॉधी जी 1917 में 'गुजरात एजुकेशन सोसायटी' के सम्मेलन में उजागर किया तथा शिक्षा में मातृभाषा के स्थान और हिन्दी के पक्ष को राष्ट्रीय स्तर पर तार्किक ढंग से रखा। स्वतन्त्रता के पश्चात् भारत में ब्रिटिशकालीन शिक्षा पद्धति में परिवर्तन के कुछ प्रयास किये गये। इनमें 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति उल्लेखनीय है। 1976 में भारतीय संविधान में संशोधन द्वारा शिक्षा को समवर्ती –सूची में सम्मिलित किया गया, जिससे शिक्षा का एक राष्ट्रीय और एकात्मक स्वरूप विकसित किया जा सके।

शिक्षा नीति का उद्देश्यः– इस शिक्षा नीति का गठन देश को 21वीं सदी की ओर ले जाने के नारे के अंगरूप में किया गया है। नए वातावरण में मानव संसाधन के विकास के लिए नए प्रतिमनों तथा नये मानवों एवं आयामों की आवश्यकता होगी। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य एक बच्चे को कुशल बनाने के साथ–साथ , जिस भी क्षेत्र में वह रूचि रखता है, उसी क्षेत्र में उन्हें प्रशिक्षण करना है। इस तरह सीखने वाले अपने उद्देश्य, और अपनी क्षमताओं का पता लगाने में सक्षम होते हैं। शिक्षार्थियों को एकीकृत शिक्षण प्रदान किया जाना है अर्थात् उन्हें प्रत्येक अनुशासन का ज्ञान होना चाहिए। उच्च शिक्षा में भी यही बात लागू होती हैं। नई शिक्षा नीति में शिक्षक की शिक्षा और प्रशिक्षण प्रक्रियाओं के सुधार पर भी जोर दिया गया है।कहा भी हैः–

शिक्षार्थी शिक्षकः शिक्षा , शिक्षाकेन्द्राणि तथैव च ।

ऐतेषामेव योगेन देशोस्माकं प्रवर्धताम् ।।

नए विचारों को रचनात्मक रूप में आत्मसात् कटने में नई पीढी को सक्षम होना चाहिए। इसके लिए बेहतर शिक्षा की आवश्यकता है। साथ ही नई शिक्षा नीति का उद्देश्य आधुनिक तकनीक की आवश्यकताऍ पूरी करने के लिए उच्चस्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त श्रम शक्ति को जुटाना है, क्यों कि इस शिक्षा नीति के आयोजनों के विचार से इस समय देश में विधमान श्रमशक्ति यह आवश्यकता पूरी नहीं कर सकती।

नई शिक्षा नीति की विशेषताऍः–

1. नवोदय विद्यालयः–नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत देश के विभिन्न भागों में विशेषकर–अचंलों में नवोदय विद्यालय खोले जायेंगे, जिनका उद्देश्य प्रतिभाशाली छात्रों को बिना किसी भेदभाव के आगे बढने का अवसर प्रदान करना होगा। इन विद्यालयों में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम लागू होगा।
2. रोजगार परक शिक्षा–नवोदय विद्यालयों में शिक्षा रोजगारपरक होगी तथा विज्ञान और तकनीक उसके आधार होंगे। इससे विद्यार्थियों को बेरोजगारी का सामना नहीं करना होगा।
3. 10+2+3 का पुनर्विभाजनः– इस विद्यालयों में 10+2+3 पद्धति पर आधारित होगी। ''त्रिभाषा फार्मूला'' चलेगा जिसमें अग्रेंजी , हिन्दी एवं मातृ भाषा या एक अन्य प्रादेशिक भाषा रहेगी। सत्रार्द्ध प्रणाली (सेमेस्टर–प्रणाली) माध्यमिक विद्यालयों मे लागू की जायेगी अंकों के स्थान पर विधार्थियों को ग्रेड दिये जायेंगे।

नई शिक्षा नीति के मुख्य बिन्दुः–

1. पहले कक्षा X एवं कक्षा XII के पेर्ट को फॉलो किया जाता था परन्तु अब नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (छम्ब्) के अन्तर्गत 5+3+3+4 का पैटर्न लागू किया जायेगा जिससे 12 वर्ष की स्कूल शिक्षा होगी और 3 वर्ष की फ्री स्कूल शिक्षा होगी। कक्षा ट्प से व्यवसायिक परीक्षण इंटर्नशिप प्रारम्भ कर दी जायेगी। यही नई शिक्षा नीति 2022 का मुख्य उद्देश्य है।
2. इस नीति के तहत 3 से 18 वर्श तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अन्तर्गत रखा गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिटी 2020 का उद्देश्य सभी छात्रों को उच्च शिक्षा करना है। 2005 तक पूर्व माध्यमिक शिक्षा (3 से 6 वर्ष तक की आयु सीमा) को सार्वभौमिक बनाना।
3. इस नीति के अन्तर्गत सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किये गये है, जिसमें 2030 तक सकल नमांकन अनुपात को 100प्रतिशत तक लाना शामिल है। शिक्षा के क्षेत्र पर केन्द्र व राज्य सरकार की मदद से जीडीपी का 6 प्रतिशत हिस्सा व्यय करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है।
4. इस नीति में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षक की है। क्यों कि शिक्षक राष्ट्र निर्माता होता है, शिक्षा नीति मे जो भी परिवर्तन हुए है उनको शिक्षक समझ कर विधार्थियों व अभिभावाकों को समझाने की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षक ही निभा रहें। शिक्षकों की भी जिम्मेदारी बढी है।
5. नई स्कूली शिक्षा प्रणाली के अनुसार बच्चे पॉच वर्ष फाउंडेशनल STAGEesa] 3 वर्ष प्रिपरेटरी स्टेज में, 3 साल मिडिल स्टेज में और 4साल सैकेण्डरी स्टेज में बिजाएंगे।

   वर्तमान शिक्षा प्रणाली वर्ष 1986 की मौजूदा शिक्षा नीति में किये गए परिवर्तनों का परिणाम है। इसे शिक्षार्थी और देश के विकास को बढावा देने के लिए लागू किया गया है। नई शिक्षा नीति बच्चों के समक्ष

विकास पर केन्द्रित है। इस नीति के तहत वर्ष 2023 तक अपने उद्देश्य को प्राप्त करने का लक्ष्य है। साथ ही यह शिक्षा नीति एक सुनियोजित व्यवस्था, साधन सम्पन्नता और लगन की मॉग करती है। यदि नई शिक्षा को ईमानदारी और तत्परता से कियान्वयन किया जाय तो निश्चय ही हम अपने लक्ष्य प्राप्ति की तरफ बढ सकेंगे।

नई शिक्षा शिक्षा नीति 2020 के तहत सकल नामांकन अनुपात को वर्ष 2030 तक सौ प्रतिशत लाने का टारगेट रखा गया है नई शिक्षा नीति 2020 में पुरानी शिक्षा नीति की खामियों को हटाकर नये पाठ्यक्रम को लाया गया है। इसमें इस बात का खास ख्याल रखा गया है कि पाठ्यक्रम सरल और सहज हो जो विधार्थियों की समझ में आ सके।

नई शिक्षा नीति के बदलते लाभ आयामः–

1. सरकार का लक्ष्य (NEP) नई ईपी 2020 की मदद से सभी को अनिवार्य रूप से स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराना है।
2. इस नये तरीके से लगभग दो करोड स्कूली छात्र शिक्षण संस्थानों में वापस आ सकेंगे। (READMORE-NEW EDUACTION POLICY) राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 2020 के अनुसार 5+3+3+4 संरचना मौजूदा 10+2 संरचना का स्थान लेगी। यह संरचना छात्र के सीखने के प्रारम्भिक वर्शों पर केन्द्रित है। यह 5+3+3+4 संरचना 3 से 8, 8 से 11, 11से 14 और 14 से 18 वर्ष की आयु से मेल खाती है। 12 वर्ष की स्कूल शिक्षा 3 वर्ष अगर आंगन बाडी और प्री–स्कूलिंग को इस संरचना में शामिल किया जाता है ।
3. 8वर्ष की आयु तम के बच्चों के लिए प्रारम्भिक बालयावस्था देखभाल और शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या और शैक्षणिक ढॉचा एनसीई आरटी द्वारा डिजायन और विकसित किया जायेगा।
4. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा मंत्रालय को मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पर एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित करना है। कक्षा ।।। तक सभी छात्र/छात्राओं के लिए संख्यात्मकता और साक्षरता की नींव को प्राप्त करने के सफल कार्यान्वयन की जिम्मेदारी भारत के राज्यों पर आती है। यह कार्यान्वयन भी 2025 तक किया जाना निर्धारित है।
5. (NEP) 2020 की खूबियों में से एक भारत में राष्ट्रीय पुस्तक विचार नीति का गठन है। परख राष्ट्रीय शिक्षा नीति सरकार द्वारा स्थापित की जानी है।
6. भारत के प्रत्येक राज्य/जिले में विशेष डे–टाईम , बोर्डिग स्कूल ''बाल भवन स्थापित किये जायेंगे। इस बोर्डिंग स्कूल का उपयोग खेल, कैरियर, कला से जुडी हुई गतिविधियों में भागीदारी के लिए किया जायेगा।
7. राष्ट्रीय शिक्षानीति 2020 के अनुसार एकेदमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना की जायेगी। छात्र/छात्राओं द्वारा अर्जित क्रेडिट को संग्रहीत किया जा सकता है और जब अंतिम डिग्री पूरी हो जाती है तो उन्हें गिना जा सकता है। साथ ही उपयुक्त अधिकारी ग्रेड 3,5, और 8 के लिए स्कूल परीक्षा आयोजित करेंगे। ग्रेड 10 और 12 के लिए बोर्ड परीक्षा जारी रहेगी। लेकिन NEP 2020 का उद्देश्य समग्र विकास के साथ संरचना को फिर से डिजायन करना है

8. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार देश में ।।। और ।। के समकक्ष बहुविशयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय स्थापित किये जायेंगे। इन्हें बहुविषयक अकादमिक शुरू करने के लिए स्थापित किया जाना निर्धारित है।

9. सार्वजनिक और निजी शैक्षणिक निकायों दोनों के मार्गदर्शन के लिए मान्यता और विनियमन नियमों की एक ही सूची का उपयोग किया जायेगा चरण बद्ध तरीके से कॉलेज सम्बद्धता और कॉलेजों को स्वायत्तता प्रदान की जायेगी।

10. वर्श 2030 तक अध्यापन के व्यवसाय से जुडने के लिए कम से कम चार वर्षीय की एड डिग्री होना अनिवार्य होगा। छात्र/छात्राओं को भविष्य में महाभारी की स्थिति के लिए तैयार करने के लिए ऑनलाइन शैक्षणिक को बडे पैमाने पर बढावा दिया जायेगा।

कार्यान्वयनः–नई शिक्षा नीति 30 वर्षो बाद आई और भारत की मौजूदा शैक्षणिक प्रणाली को अन्तरराष्ट्रीय स्तर के शैक्षणिक स्तर के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से बदलने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारत सरकार का लक्ष्य वर्ष 2040 तक (छम्च्) इन ईपी की स्थापना करना है। लक्षित वर्ष तक, योजना के मुख्य बिन्दू को एक–एक करके लागू किया जाना है। (छम्च्) द्वारा प्रस्तावित सुधार केन्द्र और राज्य सरकार के सहयोग से लागू होगा। कार्यान्वयन रणनीति पर चर्चा करने के लिए केन्द्र और राज्य दोनों स्तर के मंत्रालयों के साथ भारत सरकार –द्वारा विशयवार समितियों का गठन किया जायेगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनेक बदलते आयाम स्थापित होगें, जो छात्र/छात्राओं के हित में होंगे।

यथाः–1. छात्र/छात्रा अब बोर्ड परीक्षा से नहीं उरेंगे

2. मातृभाषा एवं क्षैत्रिय भाषाओं का महत्व मिलेगा।

3. महाविद्यालय छोडने वालों को फायदा होगा।

4. छात्र/छात्रा आत्मनिर्भर बनेंगे।

राष्ट्रीय शिक्षानीति की एक विशेषता यह रहेगी कि संस्कृत को स्कूल में मजबूत पेशकश के साथ ''मुख्यधारा'' में शामिल किया जायेगा जिसमें त्रि–भाषा फॉर्मूले में एक भाषा विकल्प भी शामिल है–

साथ ही उच्च शिक्षा में भी। संस्कृत विश्वविद्यालय भी उच्च शिक्षा के बड़े बहुविषयक संस्थान बनने की दिशा में आगे बढेंगे। भारतीय भाषाओं के शिक्षण और सीखने को हर स्तर पर स्कूली और उच्च शिक्षा के साथ एकीकृत करने की आवश्यकता है। भाषाओं को प्रासांगिक और जीवन्त बनाए रखने के लिए, इन भाषाओं में पाठ्य पुस्तकों, कार्यपुस्तिकाओं, वीडियो, नाटकों, कविताओं, उपन्यासों, पत्रिकाओं आदि सहित उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षण और मुद्रित सामग्री की एक सतत धारा होनी चाहिए। नीति उत्कृष्ट स्थानीय कलाकारें, लेखकों, शिल्पकारों और अन्य विशेषज्ञों को मास्टर प्रशिक्षकों के रूप में नियुक्त करने का भी सुझाव देती है। मानविकी विज्ञान, कला, शिल्प और खेल आदि में आदिवासी और अन्य स्थानीय ज्ञान सहित पारंपरिक भारतीय ज्ञान को पाठ्यक्रम में सटीक शामिल करना। प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान में और प्रत्येक स्कूल एवं परिसर का लक्ष्य छात्रों को कला,रचनरत्मकता और क्षेत्र। देश के समृद्ध खजाने से परिचित कराने के लिए निवास में कलाकार रखना। पूरे देश में भारतीय भाषाओं, तुलनात्मक साहित्य, रचनात्मक लेखन, कला, संगीत, दर्शन आदि में जमबूत विभाग और कार्यक्रम शुरू और विकसित किये जायेंगे और चार वर्षीय बी.एड. सहित डिग्री प्रदान की जायेगी, तथा इन विषयों में दोहरी डिग्री

विकसित की जायेगी। उच्च शिक्षा प्रणाली के भीतर अनुवाद और व्याख्या,कला और संग्रहालय प्रशासन, पुरातत्व, कलाकृति संरक्षण, ग्राफिक डिजायन और बेबडियन में उच्च गुणवता वाले कार्यक्रम और डिग्री भी बनाये जायेंगे। तथा द्विभाषी रूप से कार्यक्रम भी पेश हो पायेंगे।

निष्कर्षः—नई शिक्षा नीति की शुरूआत की शुरूआत के साथ, कई बदलाव किये गये है और उनमें से एक एम.फिल कोर्स को बन्द करना है। हर चीज के दो पहलू के होते है। एक अच्छा और दूसरा बुरा। नई शिक्षा नीति से देश की मौजूदा शिक्षा प्रणाली में व्याप्त खामियों को दूर करने में मदद मिल सकती है, उन्होनें आंशका जताई कि भूशिक्षा नीति के कुछ प्रावधानों की वजह से देश में शिक्षा के निजीकरण, केन्द्रीयकरण, नौकरशाही ए का दबदबा, शिक्षकों की स्वायत्तता को नुकसान एवं मुनाफाखोरी जैसी प्रवृतियों को बढावा मिल सकता है। सार्वजनिक निधि से पोषित सरकारी महाविद्यालयों की फंडिग का पेंटर्न बदलने से शिक्षा के सार्वजनिकीकरण के उद्देश्यों की पूर्ति मुश्किल हो जायेगी। अतः नई शिक्षा नीति 2000 में पुरानी नीति की खामियों को हटाकर नये पाठ्क्रमो को हटाकर नये पाठ्यक्रमो को लाया गया है। इसमें इस बात का खास ख्याल रखा गया है कि पाठ्यक्रम सरल और सहज हो, जो विद्यार्थियों की समझ में आ सके।

***प्राचार्य**
राजकीय लक्ष्मीनाथ शास्त्री संस्कृत
महाविद्यालय, चीथवाड़ी (जयपुर)

संदर्भः—

1. www.utamhindu.com/politics/150172/new-education-policy-foundation
(नई शिक्षा नीति—नए भारत की नींव, 2 अंग.,2020)
2. दृष्टि, The vision (चर्चित मुद्दे) नई शिक्षा नीति, 2020
3. मनुस्मृति **(मनु.2/20)**
4. गंगवाल सुभाष, नई शिक्षा नीति ईकस्वी सदी की चुनौतियों का करेगी मुकबला दैनिक नई ज्योति पृष्ठ संख्या 4 , 22 अगस्त 2020
5. प्रो. के.एल.शर्मा दैनिक भास्कर जयपुर संरूकरण पृष्ठ संख्या 2, 24 अगस्त 2020
6. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार।
7. ईकस्वी सदी की मांग पूरी करेगी नई शिक्षा नीति संस्कृत शिक्षा के क्षेत्र में भी आउटलुक 24 अगस्त 2020

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्दुःखभग्भवेत्।।